एकीकृत लॉजिस्टिक योजना के तहत औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव नोडल अधिकारी बने

यूपी में उद्योगों की सहूलियत के लिए नई योजना

फैसला

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

यूपी सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन के तेजी से विकास के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना तैयार की है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वह नवगठित लॉजिस्टिक सेल के अध्यक्ष होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाने और राज्य में सुदृढ़ लॉजिस्टिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए यह कदम उठाया गया है। उद्योगों की सुविधा के लिए आपूर्ति सप्लाई चेन और भण्डारण सुविधाओं के विकास के लिए लॉजिस्टिक सेल केंद्र सरकार के लॉजिस्टिक डिविजन से समन्वय कर काम करेगा। राज्य सरकार के नियोजन, परिवहन, नागरिक उड्डयन, राजस्व, लोक निर्माण, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) विभाग सेल के प्रमुख सदस्य होंगे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आदि के नोडल अधिकारी सेल में विशेष आमंत्री होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सप्लाई चेन में अवरोधों के मद्देनजर इस प्रकार की योजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन के विकास के लिए समन्वित व केन्द्रित कार्यवाही हो सकेगी।

देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब यूपी में

एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के साथ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) का जंक्शन ग्रेटर नोएडा के दादरी में है। अतः इसको भारत में सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य में बोडाकी और वाराणसी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश निजी लॉजिस्टिक पार्क नीति घोषित करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है।

इन मानदंडों पर होगा काम

- सुदृढ़ लाजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार छह मापदंडों पर कार्य करेगी
- प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था में सुगमता
- लॉजिस्टिक्स अवस्थापना की गुणवत्ता
- कार्गो परिवहन की सुरक्षा
- विनियामक प्रक्रिया (रेगुलेटरी प्रॉसेस) की दक्षता